



वित्त मंत्री

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल

का

वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

आदरणीय अध्यक्ष जी,

1. मैं सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। उत्तराखण्ड राज्य की विकास यात्रा में सम्मिलित सभी कर्मयोगियों को मैं, प्रणाम करता हूँ। इस अवसर पर मैं उत्तराखण्ड की देवभूमि, तपोभूमि, वीरभूमि और खेलभूमि का वंदन करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य का सपना साकार करने वाले परम श्रद्धेय स्व० श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुखार बिन्दुओं को दोहरा रहा हूँ:-

“यह वन्दन की भूमि है,

अभिनन्दन की भूमि है।

यह तर्पण की भूमि है,

यह अर्पण की भूमि है।

इसका कंकर-कंकर शंकर है,

इसका बिन्दु-बिन्दु गंगाजल है।”

2. इस वर्ष हम उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की “रजत जयंती” मना रहे हैं। देवभूमि उत्तराखण्ड मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठ अन्नदाता व उद्यमी आदि की महत्वपूर्ण भागीदारी से सशक्त उत्तराखण्ड के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हैं।
3. हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण के मार्ग पर पारदर्शिता के साथ निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। हम अग्रणी राज्यों की पंक्ति में अपना स्थान बनाने और अपने राज्य की समृद्धि और सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर हैं।

4. परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत @2047 के लिए न केवल सशक्त वैचारिक प्रेरणा दी है अपितु विभिन्न अवसरों पर स्पष्ट कार्ययोजना भी इंगित की है। इसी प्रेरणा के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, आधारभूत अवसंरचना का विकास, मानव संसाधन विकास, पर्यावरण संरक्षण व समावेशी विकास हमारी सरकार की विभिन्न योजनाओं के केंद्र बिंदु हैं।
5. “विकसित उत्तराखण्ड” की अवधारणा में सर्वांगीण, समावेशी व सतत विकास, सुशासन, सहभागिता व समरसता निहित है। यह बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का दर्पण है। हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में सुधार और विकास की राह दिखाई है। यह बजट पूर्व में लिए गए संकल्पों के सापेक्ष अर्जित सिद्धि का प्रमाण है तथा भविष्य के लिए एक रोडमैप है।
6. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता से किये गये वायदे को पूर्ण करते हुए 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी गयी है। यह अत्यन्त गर्व का विषय है कि हमारा प्रदेश परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से स्वतन्त्रता के उपरान्त समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। यह संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप सभी नागरिकों को समान अधिकार देते हुए हमारी मातृशक्ति के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है।

समान नागरिक संहिता पंचामृत अर्थात् पाँच तत्वों का प्रतिबिम्ब है:

समरसता, समानता, सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण।

यह नए युग का आरम्भ है।

7. आदरणीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार के आशीर्वाद से हमारे राज्य को इस वर्ष भी कुछ बड़े अवसर प्राप्त हुए हैं। यह गौरव का विषय है कि राज्य गठन के उपरान्त पहली बार देवभूमि उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का

अवसर प्राप्त हुआ। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर किया गया। यह आयोजन उत्तराखण्ड को खेलभूमि के रूप में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा है। देवभूमि की मेजबानी को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।

8. राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में **24 स्वर्ण, 35 रजत, 44 कांस्य पदक** के साथ **कुल 103 पदक** प्राप्त करते हुए सातवे स्थान पर पहुंचकर उत्तराखण्ड ने इतिहास रचा है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड 25वें स्थान पर था। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कुल पदकों की संख्या के आधार पर उत्तराखण्ड का स्थान चौथा है।
9. **38वें राष्ट्रीय खेलों** का ऐतिहासिक आयोजन राज्य की खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों का दर्पण है तथा भविष्य में उत्तराखण्ड के खेल जगत के लिए महान प्रेरणा भी है।
10. राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से प्रदेश के युवाओं को अभूतपूर्व प्रेरणा मिली है। आज एक मजबूत खेल इकोसिस्टम बन चुका है। हमारी सरकार द्वारा उच्च स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर सृजित किया गया है। रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) में वैलोड्रम का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि समूचे उत्तर भारत में दिल्ली के अतिरिक्त मात्र उत्तराखण्ड राज्य में ही वैलोड्रम बनाया गया है। जनपद देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में ओलम्पिक प्रतियोगिता के स्तर का शूटिंग रेंज बनाया गया है। खेलों के लिए तैयार की गई ऐसी अनेक सुविधाओं का लाभ राज्य के खिलाड़ियों की दक्षता बढ़ाने तथा नये अवसर प्रदान करने में किया जायेगा।
11. हमारे राज्य को दिसम्बर 2024 में **वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो – 2024** सम्मेलन की मेजबानी का गौरवपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। यह सम्मेलन आयुर्वेद

के क्षेत्र में परस्पर ज्ञान साझा करने, शोध कार्यों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है।

12. अध्यक्ष जी, वित्तीय वर्ष 2024–25 अभिनव पहल का वर्ष रहा है। इस संदर्भ में यहाँ कुछ प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख किया जा रहा है:—

- इस वर्ष से हमारी सरकार ने शीतकालीन यात्रा की एक अनूठी पहल शुरू की है। इस प्रयास से एक ओर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी मजबूती मिलेगी।
- जनवरी, 2025 में देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन हमारी सरकार की एक अभिनव पहल रही है। यह सम्मेलन, विदेशों में रहने वाले उत्तराखण्ड के प्रवासी भाई-बहनों को अपनी मिट्टी से जोड़ने की पहल है। प्रवासियों द्वारा “गाँव को गोद लें (एडोप्ट ए विलेज)” की अवधारणा हमारे गाँवों के लिए एक नई प्रेरणा है।
- 11–12 फरवरी 2025 को देवभूमि उद्यमिता योजना के अन्तर्गत देहरादून में मेगा स्टार्टअप समिट का आयोजन हुआ। यह अभिनव प्रयास शिक्षण संस्थानों को शिक्षण व अनुसंधान के साथ-साथ नवाचार और उद्यमशीलता के केन्द्र बनने के लिए एक सशक्त प्रेरणा है।
- हमने उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली कानून – 2024 को प्रदेश में लागू किया है। इस कानून में दंगाइयों और उपद्रवियों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली करने का प्रावधान किया गया है।
- प्रदेश में तीन नए अपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 01 जुलाई 2024 से लागू किए गये हैं।

- इकोनॉमी व इकोलॉजी के मंत्र के साथ हमारा राज्य ग्रॉस डोमिस्टिक प्रोडक्ट (जी.डी.पी.) की तर्ज पर ग्रॉस एन्वायरमेंट प्रोडक्ट (जी.ई.पी.) का भी आंकलन कर रहा है। जल, जमीन, जंगल और हवा को समाहित कर जी.ई.पी. सूचकांक बनाया गया है।
- नगर निगम रूद्रपुर में लगभग 30 साल पुराने शहरी ठोस अपशिष्ट का कायाकल्प कर ट्रेचिंग ग्राउंड को एक सुन्दर स्थान में परिवर्तन करते हुए वेस्ट टू वंडर्स को चरितार्थ किया है।
- परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के अन्तर्गत माँ के नाम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। माँ व धरती—माँ, से सम्बद्ध यह भावनात्मक अपील वृक्षारोपण अभियान को सफल बनायेगी।
- पर्यटन विभाग द्वारा राज्य में पहली बार “एस्ट्रो टूरिज्म” को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से नक्षत्र सभा का आयोजन जॉर्ज एवरेस्ट (मसूरी), जागेश्वर (अल्मोड़ा), ताकुला (नैनीताल) व बेनीताल (चमोली) में किया गया है।
- समावेशी व संतुलित विकास हेतु हिमाच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका मासिक विद्युत उपभोग 200 यूनिट तक है तथा अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिनका अनुबन्धित विद्युत भार 01 किलोवाट तक तथा मासिक विद्युत उपयोग 100 यूनिट तक है, को विद्युत दरों में 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- गरीब परिवारों को सस्ते पोषण युक्त नमक की आपूर्ति शुरू की गई है।
- ऋषिकेश ऐम्स से देश की पहली हेली एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है।

13. आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सफल कार्यनीति पर मोहर लगाते हुए यह वर्ष अनेक उपलब्धियों का साक्षी रहा है। इस वर्ष भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखण्ड सरकार की उपलब्धियों को सराहा गया है। यहाँ कुछ उपलब्धियों का उल्लेख किया जा रहा है:-

- नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी इंडेक्स) 2023-24 की रिपोर्ट में देश में उत्तराखण्ड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहना हम सबके लिए गौरवान्वित होने का अवसर है। शीर्ष स्तर पर बने रहना एक चुनौती भी है। इसीलिए इस बात का विशेष प्रयास किया जा रहा है कि सभी विभाग अपने से सम्बन्धित इंडीकेटर्स में शीर्ष प्रदर्शन करें। इस हेतु मॉनिटरिंग को सुदृढ़ किया जा रहा है।
- औद्योगिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों को भारत सरकार ने सराहा है। हमारे प्रदेश को "लाजिस्टिक्स ईज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स" (लीड्स) पहल में "टॉप एचीवर्स" के रूप में मान्यता दी गई है। यह सम्मान राज्य में लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है।
- स्टार्ट-अप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को "लीडर" श्रेणी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑनलाईन सिंगल विंडो के लिए "टॉप एचीवर्स" श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये उपलब्धियां औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल परिवेश निर्माण के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
- आई.सी.आर.टी इंडिया और उपमहाद्वीप पुरस्कार-2024 के संस्करण में स्थानीय समुदायों को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड को “सिल्वर अवॉर्ड” प्रदान किया गया है।

- विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तराखण्ड के चार गांवों – सूपी (बागेश्वर), गुंजी (पिथौरागढ़) एवं जखोल व हर्षिल (उत्तरकाशी) को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- उत्तराखण्ड को मत्स्य पालन के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हिमालयी और उत्तर पूर्व के राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2024 में उत्तराखण्ड राज्य को स्वच्छ मंडप के क्षेत्र में विशेष प्रशंसा पदक से पुरस्कृत किया गया है।
- गणतंत्र दिवस परेड-2025 के अवसर पर राज्य की झांकी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

14. अध्यक्ष जी, यह वर्ष प्रतिबद्धताओं के अभूतपूर्व निर्वहन का वर्ष रहा है। गत वर्ष इस सम्मानित सदन में हमने अनेक योजनाओं को संतृप्त (सैचुरेट) करने के लक्ष्य का उल्लेख किया था।

15. इसी क्रम में क्रैश बैरियर निर्माण, असुरक्षित पुल व ट्राली के सुरक्षित विकल्प, पार्किंग, सभी जनपदों में हवाई सम्पर्क सुविधा, बायो-फैन्सिंग, शासकीय अभिलेखों का डिजीटाईजेशन, सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति, पुस्तकालय की स्थापना एवं सुदृढीकरण, थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्र की स्थापना, सरकारी भवनों में सोलर एनर्जी सिस्टम, ई-ऑफिस क्रियान्वयन एवं पंचायत भवनों की स्थापना की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

16. इस वर्ष हमने गोला नदी पर जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना एवं सौंग नदी पर सौंग बाँध पेयजल परियोजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा रानीखेत शहर की पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण गगास बैराज का निर्माण पूर्ण किया है।
17. आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अभिव्यक्त संकल्पों से प्रेरित है। सरकार द्वारा कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन, कानून के पालन में गर्व का भाव, संविधान का सम्मान, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, हर क्षेत्र व समाज को विकास का समान अवसर, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, सांस्कृतिक विरासत पर गर्व, प्रदेश के विकास के माध्यम से राष्ट्र का विकास तथा "एक भारत—श्रेष्ठ भारत" के लक्ष्य को सर्वोपरि रखने के संकल्प की प्रेरणा से हम विकास की यात्रा पर अनवरत आगे बढ़ रहे हैं।
18. अध्यक्ष जी, हमारा यह बजट अंगेजी भाषा के चार वर्ण **N, A, M** और **O** (नमो) यानि नवाचार, आत्मनिर्भर, महान विरासत व ओजस्वी से समझा जा सकता है।
- 18 (क) सर्वप्रथम "नमो" के प्रथम बिन्दु 'N' अर्थात् नवाचार की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी, डिजिटल गवर्नेंस, शोध व विकास, नई प्रौद्योगिकी तथा स्टार्ट—अप के अनुरूप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित कर नवाचार को नये आयाम दे रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नवाचार की व्यापक प्रेरणा के लिए विभिन्न विभागों में गेम चेंजर योजनाओं के चिन्हिकरण एवं क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है। नवाचार से प्रेरित कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है:—
- "परिवार पहचान पत्र उत्तराखण्ड" योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट आई0डी0 उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। इस योजना के

क्रियान्वयन से लाभार्थीपरक योजनाओं का बेहतर प्रबन्धन, समयबद्ध लक्ष्यपूर्ति एवं पारदर्शी संचालन होगा।

- डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) हेतु ई-रूपी का क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया गतिमान है। ई-रूपी नकदी (कैश) का डिजिटल प्रारूप है। इससे लक्षित लाभ की पूर्ति सुनिश्चित होगी तथा धनराशि के डाईवर्जन को रोका जा सकेगा। उद्यान, कृषि तथा अनेक विभागों में सामग्री के रूप में वितरित की जाने वाली सहायता, ई-रूपी के माध्यम से बेहतर संचालित हो सकेगी।
- केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन में दक्षता लाने के लिए केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए 'एस.एन.ए.-स्पर्श' (सिंगल नोडल एजेन्सी-समयोचित प्रणाली शीघ्र हस्तान्तरण) व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने इन्टीग्रेटेड फाईनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS), पब्लिक फाईनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के इंटीग्रेशन द्वारा यह व्यवस्था प्रदेश में भी ऑनबोर्ड कर दी है। सात (7) योजनाओं में जनवरी 2025 तक एस.एन.ए. स्पर्श योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक भुगतान किया जा चुका है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट समयावधि में लक्ष्य पूरा करने के लिए राज्यों के लिए पूंजीगत सहायता योजना (SASCI) के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली राशि के लिए हमने अर्हता भी प्राप्त कर ली है।
- "हाउस ऑफ हिमालयाज" योजना के अन्तर्गत हम अपने पारंपरिक उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधीय जड़ी-बूटियों और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

- सतही विद्युत टरबाईन के शोध एवं विकास हेतु उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के मध्य समझौता प्रपत्र हस्ताक्षरित किया गया है।
- नगर पंचायत, बद्रीनाथ द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम में पूजा उपरान्त इकट्ठा किये गये फूलों से अगरबत्ती बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है।
- मानवीय हस्तक्षेप समाप्त करने, बिलिंग सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण तथा विद्युत खपत को बेहतर तरीके से प्रबन्ध करने के उद्देश्य से यूपीसीएल द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है।
- पेपरलेस रजिस्ट्रेशन (स्टॉम्प एवं निबन्धन विभाग), बायोमैट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण (राज्य कर विभाग), इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (परिवहन विभाग), मोबाईल फॉरेंसिक वैन व ड्रोन सैल (गृह विभाग), ऊर्जा दक्ष पंप, फायर हाइड्रेंट मशीन व स्मार्ट मीटर (पेयजल विभाग), इनोवेटिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक (लोक निर्माण विभाग), नलकूप एवं लिफ्ट योजनाओं में स्प्रिंकलर प्रणाली (सिंचाई विभाग) एवं विज्ञान चेतना केंद्र, साईंस सेंटर, साईंस सिटी, लैब ऑन व्हील्स तथा स्मार्ट क्लास ऐसे अनेक नवाचारों को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। विद्यार्थियों हेतु देवभूमि उद्यमिता योजना भी हमारी सरकार का महत्वपूर्ण नवाचार है।

18 (ख) आदरणीय अध्यक्ष जी, अब "नमो" के द्वितीय बिन्दु 'A' अर्थात आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। राष्ट्रऋषि परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर हम इस बजट में सात (7) बिन्दुओं पर विकास के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं:-

- (I) कृषि
- (II) उद्योग
- (III) ऊर्जा
- (IV) अवसरचना
- (V) संयोजकता
- (VI) पर्यटन
- (VII) आयुष

ये "सप्तऋषि" समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखण्ड के आधार है।

(i) आदरणीय अध्यक्ष जी, इस क्रम में आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के लिए सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:-

- परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जैविक खेती का विस्तार किया जा रहा है। जैविक खेती भूजलस्तर के संरक्षण में भी सहायक है एवं पर्यावरण व मनुष्य दोनों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है।
- श्री अन्न (मिलेट) के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेट मिलेट मिशन प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश में 2021-22 में मंडुआ समर्थन मूल्य कुल ₹0 2,500 प्रति कुंतल था, जो 2024-25 में ₹0 4,200 प्रति कुंतल हो गया है। इस तरह दो साल के अंतराल में ही समर्थन मूल्य 68 प्रतिशत बढ़ गया है। अन्नदाता प्रेरित होकर मंडुआ उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ा रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालयाज के माध्यम से भी मंडुआ उत्पादों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
- राज्य में एप्पल और कीवी मिशन के तहत तेजी से कार्य किये जा रहे हैं। सेब के उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पैकेजिंग और मार्केटिंग की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सेब और कीवी उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में सहायक होंगे।

- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत जनपद उधमसिंहनगर में 02 वृहद प्रोजेक्ट राज्य स्तरीय इण्टीग्रेटेड एक्वा पार्क तथा होलसेल फिश मार्केट की स्थापना का कार्य गतिमान है।
 - मा0 सहकारिता मंत्री, भारत सरकार द्वारा बंदी गाय घी की लांचिंग की गई है। बंदी गाय घी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ बंदी गाय घी की जी0आई0 टैगिंग करायी जा रही है। यह कदम हमारे गौ पालकों के प्रयासों को बड़े अवसर प्रदान करेगा।
 - हमारी सरकार द्वारा ऐरोमैटिक सेक्टर के विकास द्वारा किसानों की आय बढ़ाने की कार्यनीति बनायी गयी है।
 - कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्पादन से लेकर विपणन तक सहायता व मार्गदर्शन प्रदान करने की व्यवस्था बनाई गयी है। बीज, खाद, उपकरण आदि पर सब्सिडी दी जा रही है।
- (ii) आदरणीय अध्यक्ष जी, अब दूसरा बिन्दु "उद्योग" की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार द्वारा स्टार्ट-अप व एम0एस0एम0ई0 (MSME) अनुकूल इको सिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। औद्योगिक परिवेश में सुधार के लिए हमारी सरकार की कुछ उपलब्धियों का पूर्व में उल्लेख किया गया है। हमारी सरकार औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है। इसी क्रम में सिडकुल (SIIDCUL) द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है:-
- उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिये हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र में 194 करोड़ रू0 की लागत से प्लैटिड फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। इससे छोटे उद्यमी मशीनरी लगाकर सीधे उत्पादन शुरू कर

सकेंगे। फ्लैटिड फैक्ट्री, सेलाकुई एवं पंतनगर की भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

- पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र में 6.38 एकड़ भूमि पर वेयर हाउस का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उद्योगों द्वारा वेयर हाउस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के दृष्टिगत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
 - काशीपुर में 133 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर तथा 40 एकड़ भूमि पर एक एरोमा पार्क विकसित किया जा रहा है।
 - सितारगंज फेज-2 में लगभग 40 एकड़ भूमि में प्लास्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है।
 - 80 एकड़ भूमि में खानपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट का कार्य गतिमान है।
 - इस बजट में औद्योगिक परिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता हेतु रू0 पचास करोड़ (रू0 50.00 करोड़), मेगा इंडस्ट्रियल/मेगा टेक्सटाइल नीति हेतु रू0 पैंतीस करोड़ (रू0 35.00 करोड़) तथा प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट अप और एंटरप्रीनियोरशिप योजना हेतु रू0 तीस करोड़ (रू0 30.00 करोड़) सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं।
- (III) अध्यक्ष जी, तीसरे बिन्दु 'ऊर्जा' की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। ऊर्जा सेक्टर के सम्बन्ध में सरकार परियोजना निर्माण में आ रही कठिनाईयों को दूर करने तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं को तीव्रता से सम्पादित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। ऊर्जा क्षेत्र में किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:—
- मदमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना (15 मेगावाट) का कार्य पूर्ण कर सितम्बर 2024 से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ढकरानी विद्युत गृह के एक मशीन के रिंग मेन यूनिट (आर.एम.यू.) कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।

- उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० द्वारा बैटरी इनर्जी स्टोरेज स्कीम (BESS) की तीन परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
- उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि० द्वारा राज्य में अत्याधुनिक ओटोमेटेड डिमान्ड रिसपॉन्स सिस्टम (ए.डी.आर.एस.) की स्थापना की जा रही है जिससे ग्रिड से ओवरड्राल की स्थिति पर नियंत्रण किया जाना सम्भव हो सकेगा।
- पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड (पिटकुल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। वाह्य सहायतित छः परियोजनाओं (लगभग रू० 520.36 करोड़) के निर्माण हेतु अनुबंध किये गए हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया जा रहा है:—
 - 132 के०वी० बाजपुर–काशीपुर लाइन एवं 132 के.वी. लोहाघाट – पिथौरागढ़ लाइन का कार्य पूर्ण किया गया है।
 - 132 के.वी. काशीपुर–बाजपुर लाइन के द्वितीय सर्किट की स्ट्रीगिंग का कार्य पूर्ण किया गया है।
 - 220 के.वी. सब स्टेशन बरम (पिथौरागढ़) को ऊर्जीकृत किया गया है।
 - 132 के.वी. सब स्टेशन भूपतवाला (हरिद्वार) पर 40 एम.वी.ए.(MVA) ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता वृद्धि की गयी है। यह ग्रीष्म ऋतु में हरिद्वार क्षेत्र में ओवर लोडिंग की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
 - 132 के.वी. सब स्टेशन पर 132 के.वी. की 'बे' (Bay) का निर्माण किया गया है।

- आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा प्रदेश वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से आच्छादित किया जा रहा है। पी0एम0 सूर्यघर योजना के क्रियान्वयन में हमारा राज्य अग्रणी राज्यों में है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 47 मेगावाट क्षमता के कुल तेरह हजार एक सौ अड़सठ (13,168) रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

(IV) अध्यक्ष जी, अब चतुर्थ बिन्दु 'अवसंरचना' विकास की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। अवसंरचना, अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। अवसंरचना में निवेश करना आत्मनिर्भर और अग्रणी उत्तराखण्ड की कुंजी है। हम गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना का निर्माण वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। हमारी सरकार अवसंरचनात्मक विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है:-

- उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र नीति-2024 का उद्देश्य चिन्हित क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र में हम बड़ी परियोजनाओं के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अवसंरचना एवं निवेश विकास बोर्ड (UIIDB) द्वारा विकसित किए जा रहे शारदा व गंगा कोरिडोर महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं से धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन के साथ स्थानीय आर्थिकी भी मजबूत होगी।
- हमारी सरकार द्वारा विभिन्न शहरों में उच्च स्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सृजित किया गया है।
- भविष्य की आवश्यकता के दृष्टिगत देहरादून में रिस्पना और बिंदाल नदियों पर फोर-लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण, देहरादून-मसूरी संयोजकता,

देहरादून रिंग रोड आदि परियोजनाओं के लिए हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

- आधारभूत अवसंरचना को समर्पित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किये गये हैं। मेगा प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत ₹0 पाँच सौ करोड़ (₹0 500.00 करोड़), जमरानी बांध परियोजना हेतु ₹0 छः सौ पच्चीस करोड़ (₹0 625.00 करोड़), सौंग परियोजना हेतु ₹0 पचहत्तर करोड़ (₹0 75.00 करोड़), लखवाड़ परियोजना हेतु ₹0 दो सौ पिचासी करोड़ (₹0 285.00 करोड़), राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता (SASCI) योजना के अन्तर्गत ₹0 एक हजार पाँच सौ करोड़ (₹0 1,500.00 करोड़), जल जीवन मिशन हेतु समग्र रूप से ₹0 एक हजार आठ सौ तैंतालीस करोड़ चौवालीस लाख (₹0 1,843.44 करोड़), नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजना का निर्माण हेतु ₹0 एक सौ करोड़ (₹0 100.00 करोड़), अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत ₹0 साठ करोड़ (₹0 60.00 करोड़) तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य हेतु ₹0 आठ करोड़ (₹0 8.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- (V) अध्यक्ष जी, पाँचवा बिन्दु "संयोजकता" की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रभावी माध्यम है। इस संदर्भ में राज्य में सड़क व हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में किये जा रहे कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:—
- सुगम्य संयोजकता के लिए राज्य में बड़े स्केल पर कार्य हो रहे हैं। आगामी वर्ष हेतु लोक निर्माण विभाग ने लगभग 220 किमी० सड़कों का नव निर्माण, 1,000 किमी० पुनर्निर्माण, 1,550 किमी० मार्ग नवीनीकरण, 1,200 किमी० पर सड़क सुरक्षा कार्य के साथ-साथ 37 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा है।

- PMGSY – 1 एवं 2 के अन्तर्गत अवशेष 17 बसावटों के संयोजन व 116 कार्य (लम्बाई लगभग-173 किमी⁰) तथा PMGSY - 3 के अन्तर्गत 191 कार्य (लम्बाई लगभग-1,759 किमी⁰) को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
- हमारी सरकार द्वारा संयोजकता के लिए नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य में विभिन्न नए स्थानों पर हैलीपैड बनाये जाने हेतु सर्वे कराया गया है।
- क्षेत्रीय सम्पर्क योजना (RCS) के अन्तर्गत 13 हैलीपोर्ट में से 8 हैलीपोर्ट – चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी), गौचर (चमोली), कोटी कॉलोनी (टिहरी गढ़वाल), श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल), फलसीमा ट्राटिक (अल्मोड़ा), हल्द्वानी (नैनीताल), सहस्त्रधारा (देहरादून) एवं मुन्स्यारी (पिथौरागढ़) का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- दिल्ली-पिथौरागढ़, सहस्त्रधारा-गौचर, देहरादून-नैनीसैनी, हल्द्वानी-मुन्स्यारी, हरिद्वार-चम्पावत तथा पिथौरागढ़-अल्मोड़ा के मध्य हवाई सेवायें संचालित हैं तथा देहरादून-नैनीताल, देहरादून-बागेश्वर, एवं देहरादून-मसूरी के मध्य हवाई सेवा प्रारम्भ करने की कार्यवाही गतिमान है।
- संयोजकता को समर्पित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किये गये हैं। पूंजीगत मद में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत लगभग ₹0 एक हजार दो सौ अड़सठ करोड़ सत्तर लाख (₹0 1,268.70 करोड़), ग्राम्य विकास के अन्तर्गत पीएमजीएसवाई हेतु ₹0 एक हजार पैंसठ करोड़ (₹0 1,065.00 करोड़), नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत लगभग ₹0 छत्तीस करोड़ अठ्ठासी लाख (₹0 36.88 करोड़) तथा बस अड्डों के निर्माण हेतु समग्र रूप से ₹0 पन्द्रह करोड़ (₹0 15.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग में

राजस्व मद में भी सड़क अनुरक्षण आदि के लिए लगभग
रु० नौ सौ करोड़ (रु० 900.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

(VI) अध्यक्ष जी, छठा बिन्दु “पर्यटन” की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। सौभाग्य से उत्तराखण्ड में पर्यटन के सभी प्रमुख आयाम जैसे कल्चरल, हिस्टोरिकल, वाइल्डलाइफ, एडवेन्चर, एस्ट्रो टूरिज्म, इको-टूरिज्म, हेल्थ एवं वेलनेस टूरिज्म की अपार सम्भावनाएं हैं। राज्य में स्थाई पर्यटन विकास सुनिश्चित करने के लिए संयोजकता, सुरक्षा और सुगमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:-

- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड के तत्वावधान में उत्तराखण्ड की समृद्ध धरोहर, जीवंत संस्कृति और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को आगंतुकों के सामने कुशलता से प्रस्तुत करने के लिए गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
- योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक पर्यटन को एकीकृत करते हुए उत्तराखण्ड को साहसिक खेलों और वेलनेस टूरिज्म के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।
- पर्यटन सेक्टर में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु नई उत्तराखण्ड पर्यटन नीति-2023 लागू की गई है। इस नीति में आवासीय परियोजनाओं हेतु अधिकतम 50 प्रतिशत तक तथा पर्यटन उत्पाद एवं सेवाओं में पूंजी निवेश को अधिकतम 100 प्रतिशत तक की अनुदान की व्यवस्था है।
- पर्यटन के क्षेत्र में 1 करोड़ से 5 करोड़ तक का निवेश करने वाले प्रदेश के स्थायी निवासियों/उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु “उत्तराखण्ड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना-2024” प्रारम्भ की गयी है।

- हमारी सरकार द्वारा सुनियोजित विकास के दृष्टिगत जागेश्वर धाम (अल्मोड़ा), महासू देवता हनोल (देहरादून) तथा जनपद चमोली में ग्राम माणा एवं टिम्मरसैण का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
- पर्यटन विस्तार के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किये गये हैं। पूंजीगत मद में पर्यटन विकास हेतु अवस्थापना निर्माण योजना के अन्तर्गत रू० एक सौ करोड़ (रू० 100.00 करोड़), टिहरी झील का विकास योजना हेतु रू० एक सौ करोड़ (रू० 100.00 करोड़), मानसखंड माला मिशन हेतु रू० पच्चीस करोड़ (रू० 25.00 करोड़), वाईब्रेंट विलेज योजनान्तर्गत रू० बीस करोड़ (रू० 20.00 करोड़), नवीन पर्यटन स्थलों का विकास अन्तर्गत रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़) तथा चार धाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं का विकास हेतु रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

(VII) अध्यक्ष जी, सातवाँ बिन्दु “आयुष” की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है।

ऋषि मुनियों संतों का तप

अनमोल हमारी थाती है।

- यह योग व आयुष की भूमि है। इसी आलोक में “आयुष” को हमारी सरकार विशेष प्रोत्साहन दे रही है। आयुर्वेद परम्परागत रूप से देवभूमिवासियों के लिए एक जीवन शैली है। हमारी सरकार विकास भी विरासत भी मंत्र के साथ आयुष का परम्परागत ज्ञान आमजन तक तथा देश व विदेश में पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। इसी उद्देश्य के साथ हमारी सरकार ने वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो-2024 का अभूतपूर्व आयोजन किया था, जिसका पूर्व में उल्लेख किया गया है। आयुष और योग के प्रचार व प्रसार द्वारा हम

फिट इंडिया मूवमेंट के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी समुचित परिवेश के निर्माण के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आयुष क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:—

- आयुष, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधीय पौधों के उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए उत्तराखंड आयुष नीति लागू की जा चुकी है।
- प्रदेश को वैश्विक योग गंतव्य के रूप में स्थापित किए जाने हेतु देश की प्रथम योग नीति प्रख्यापन की प्रक्रिया गतिमान है।
- योग विधा को सुदृढ़ किए जाने हेतु आयुष विभाग के अन्तर्गत ही योग निदेशालय स्थापित किया जाना विचाराधीन है।
- प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स (एन.ए.बी.एच.) के माध्यम से प्रत्यायन करवाया जा रहा है। प्रदेश में संचालित होम स्टे को वेलनेस सेवाओं के साथ संयोजित किया जा रहा है।
- एक समृद्ध विरासत के कारण हम धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन में अग्रणी है। हमारे पास योग और आयुर्वेद की स्वस्थ परंपरा तथा गुरुकुल और ऋषिकुल जैसे ऐतिहासिक संस्थान हैं।
- आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर प्रतिष्ठित कर पर्यटन, विरासत एवं स्वास्थ्य संरक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के द्वार खोले जा रहे हैं।

18 (ग) आदरणीय अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के आधार स्तम्भ सप्तऋषि की चर्चा के उपरान्त अब "नमो" के तीसरे बिन्दु 'M' अर्थात महान विरासत की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार "विकास भी और विरासत भी" के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। हमें देवभूमि की महान विरासत पर गर्व है। हमारी देवभूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है।

भूमि देवों की,
नदी और मेघों की,
संकल्पों की हो रही सिद्धि,
अर्थ व्यवस्था में आ रही समृद्धि।

- "विकास भी, विरासत भी" हमारा एक विजन है, जो देवभूमि के संतुलित विकास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की अवधारणा को प्रशस्त करता है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखते हुए आधुनिक विकास की ओर बढ़ते हुए हम एक ऐसे उन्नत उत्तराखण्ड की नींव रख रहे हैं, जो न केवल तकनीकी और आर्थिक रूप से उन्नत होगा, बल्कि अपनी जड़ों से भी जुड़ा रहेगा।
- हमारी सरकार द्वारा महान विरासत के संरक्षण के लिए किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है:—
 - माननीय मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यन्त, पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया है। इससे वर्षभर पहाड़ों में पर्यटन, परिवहन और व्यापार के विस्तार की सम्भावनाएं बढ़ी हैं।
 - सांस्कृतिक-आध्यात्मिक केन्द्रों में सुविधाओं के विकास पर फोकस किया जा रहा है। हमारी सरकार ने आदि कैलाश, ओम पर्वत आदि पवित्र स्थानों के लिए सड़क संयोजकता को सुगम बनाने तथा हेली सेवाओं से संयोजन करने के गम्भीर प्रयास किये हैं।
 - गोविंद घाट से घांघरिया मार्ग का नाम साहिबजादे जोरावर सिंह एवं बिड़ौरा छेवी पातशाही गेट से धूमखेड़ा मार्ग का नाम साहिबजादे फतेह सिंह मार्ग किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- हरिद्वार और ऋषिकेश के पुनर्विकास द्वारा धरोहर संरक्षण को पर्यावरणीय स्थिरता और आधुनिक सुविधाओं के साथ सहज रूप से एकीकृत किये जाने की योजना है।
- शारदा रिवर फ्रंट और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे मीठा रीठा साहिब और श्यामलताल जैसे गौरवशाली विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य व धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार ने पहल की है।
- संस्कृति के विकास और संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान इस बजट में किये गये हैं। कांवड़ मेले के आयोजन हेतु ₹0 सात करोड़ (₹0 7.00 करोड़), अर्द्धकुम्भ मेले की प्रारम्भिक तैयारी हेतु पूंजीगत मद में ₹0 दस करोड़ (₹0 10.00 करोड़), ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना हेतु लगभग ₹0 दो करोड़ चौंसठ लाख (₹0 2.64 करोड़), विभिन्न मेलों के आयोजन के लिए ₹0 एक करोड़ (₹0 1.00 करोड़), संग्रहालय भवन निर्माण हेतु ₹0 तीन करोड़ (₹0 3.00 करोड़) तथा महान विभूतियों की मूर्तियों आदि के लिए ₹0 एक करोड़ पचास लाख (₹0 1.50 करोड़) का प्रावधान इस बजट में किया गया है।

18 (घ) आदरणीय अध्यक्ष जी, "नमो" के चौथे बिन्दु '0' अर्थात ओजस्वी मानव संसाधन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार एक ऐसा परिवेश तैयार कर रही है जिसमें आगे बढ़ने की सतत प्रेरणा है। पोषण से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम, रोजगार सृजन व विपणन सभी बिन्दुओं को समेटे हुए होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जा रहा है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:-

- उत्तराखण्ड में नॉलेज इकॉनामी विस्तार की असीमित संभावनाएं हैं। देवभूमि उद्यमिता योजना, छात्रवृत्तियाँ, शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम, प्रशिक्षण तथा साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रोत्साहन, खेल सुविधाओं का विकास, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन, उद्यमिता को प्रोत्साहन, कृषकों को प्रोत्साहन सहित अनेक तरीकों से प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा है।
- हमारे युवा सिर्फ डिग्री ही नहीं, कौशल भी विकसित करेंगे तथा अर्थव्यवस्था और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी करेंगे। हमारे युवा स्टार्ट-अप के माध्यम से इनोवेटिव समाधान दे सकते हैं। हमारी सरकार द्वारा शिक्षा, खेलकूद, स्टार्ट-अप, एम.एस.एम.ई. (MSME), पर्यटन व कृषि आदि अनेक क्षेत्रों में प्रेरक परिवेश निर्मित किया जा रहा है।
- परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से प्रेरणा लेते हुए डिजिटल दक्षता, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस (AI) को उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम का अंग बनाने की प्रक्रिया गतिमान है।
- हमारी सरकार ने स्टार्ट-अप को फंड तथा मार्गदर्शन सुलभ कराने के लिए ₹0 200 करोड़ के उत्तराखण्ड वेंचर फंड की स्थापना का निर्णय लिया है। इस हेतु इस बजट में नई मांग के माध्यम से ₹0 बीस करोड़ (₹0 20.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया है।
- हमारी सरकार का विश्वास है कि ओजस्वी मानव संसाधन आत्मनिर्भर और विकसित उत्तराखण्ड की कुंजी है। हम युवा व बुजुर्ग सभी की सामूहिक ऊर्जा से आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

- आदरणीय अध्यक्षजी, गैब्रियल गार्सिया मार्खेज़ जी की प्रेरक पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

*ये सच नहीं कि
लोग बूढ़े हो जाते हैं,
इसलिए वे सपनों को
पूरा करने की धुन छोड़ देते हैं।
वे सपनों को पूरा करने की
धुन छोड़ देते हैं,
इसलिए वे बूढ़े हो जाते हैं।*

19. आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित उत्तखण्ड के लिए हमारी सरकार "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए यह बजट मानव पूंजी निवेश व क्षमता संवर्धन द्वारा समावेशी विकास का बजट है। हमारे इन प्रयासों को ज्ञान (GYAN) यानि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति के सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों से समझा जा सकता है।

19 (क) अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम ज्ञान (GYAN) के प्रथम बिन्दु 'G' अर्थात गरीब कल्याण की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। "नर सेवा नारायण सेवा है।" हमारी सरकार का यह विश्वास है कि गरीब सशक्तिकरण सिर्फ एक सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि प्रदेश की समृद्धि का आधार भी है। जब गरीब आत्मनिर्भर बनते हैं, तो न केवल उनकी स्थिति में सुधार होता है, बल्कि पूरा समाज और अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है।

*गरीबी से गौरव की ओर,
निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर,
हासिये से केन्द्र की ओर,
गरीब के हाथ में है विकास की डोर।*

- हमारी सरकार द्वारा गरीब कल्याण के लिए किये जा रहे कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है:—
 - आवास विभाग के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए **15,960** आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया गतिमान है। इनमें से 2,312 आवास लाभार्थियों को आवंटित कर दिए गए हैं। शेष आवासों का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है।
 - प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के अन्तर्गत 1,344 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है, शेष 213 आवासों को पूर्ण किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बारह लाख चौदह हजार सात सौ आठ (**12,14,708**) प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारकों को 5 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट प्रति माह तथा अन्त्योदय के एक लाख चौरासी हजार एक सौ आठ (**1,84,108**) राशन कार्डधारकों को 35 किलो ग्राम खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत नौ लाख चौरानवे हजार नौ सौ तिरानवे (**9,94,993**) कार्डधारकों को 7.5 किलो ग्राम चावल रू0 11 प्रति किलो ग्राम की दर से प्रति राशन कार्ड प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा है।
 - जून, 2024 में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत कुल तेरह लाख अठानवे हजार आठ सौ सोलह (**13,98,816**) राशन कार्ड धारक लाभान्वित हो रहे हैं।
 - मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अन्तर्गत तीन (03) गैस सिलेन्डर रिफिल की निःशुल्क सुविधा का लाभ एक लाख चौरासी हजार एक सौ आठ (**1,84,108**) अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को दिया जा रहा है।

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री-श्रम योगी मानधन योजना के अन्तर्गत राज्य में दिनांक 26 जनवरी 2025 तक उन्तालीस हजार पाँच सौ अड़तीस (39,538) श्रमिकों का नामांकन हुआ है।
- 18 राजकीय चिकित्सालयों में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड धारकों एवं बी0पी0एल0 रोगियों को निःशुल्क डायलेसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- समाज कल्याण विभाग के तत्वावधान में जनपद बागेश्वर, चमोली एवं उत्तरकाशी में वृद्धाश्रम संचालित हैं एवं देहरादून में आदर्श वृद्धाश्रम संचालित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। जनपद अल्मोड़ा एवं चंपावत में वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य गतिमान है।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग पाँच लाख इकसठ हजार तीन सौ छः (5,61,306) वृद्धजनों, दो लाख उन्नीस हजार छः सौ ईक्यावन (2,19,651) निराश्रित विधवाओं, तिरानवे हजार एक सौ चौरासी (93,184) दिव्यांगों, सत्ताइस हजार चार सौ चौरानवे (27,494) किसानों एवं सात हजार चार सौ इकत्तीस (7,431) परित्यक्त निराश्रित महिलाओं को मासिक रूप से पेंशन दी जा रही है।
- मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 03 दिसंबर 2024 से विभागीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 59 वर्ष 6 माह की आयु से ही आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है, जिससे 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही पात्र वृद्धजनों की पेंशन प्रारम्भ होने का मार्ग प्रशस्त हो सके।

- उद्योग विभाग के तत्वावधान में शिल्पी बुनकरों का संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु 285 व्यक्तियों को शिल्पी पेंशन दी जा रही है।
- औद्योगिक सस्थानों में दैनिक वेतन भोगियों एवं श्रमिकों की आवास सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु हरिद्वार में 1.13 एकड़ भूमि पर 'रेंट बेस्ड एकोमोडेशन' का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।
- आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में गरीब कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किये गए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:—
 - सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु लगभग ₹0 एक हजार आठ सौ ग्यारह करोड़ छियासठ लाख (₹0 1,811.66 करोड़), विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी हेतु लगभग ₹0 नौ सौ अठारह करोड़ बयानवे लाख (₹0 918.92 करोड़), अन्नपूर्ति योजनान्तर्गत ₹0 छः सौ करोड़ (₹0 600.00 करोड़), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु समग्र रूप से लगभग ₹0 दो सौ सात करोड़ अठारह लाख (₹0 207.18 करोड़), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु समग्र रूप से लगभग ₹0 चौवन करोड़ बारह लाख (₹0 54.12 करोड़), ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों हेतु अनुदान ₹0 पच्चीस करोड़ (₹0 25.00 करोड़), परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु ₹0 चालीस करोड़ (₹0 40.00 करोड़), राज्य खाद्यान योजना हेतु ₹0 दस करोड़ (₹0 10.00 करोड़), खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्राथमिक तथा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु लगभग ₹0 चौतीस करोड़ छत्तीस लाख (₹0 34.36 करोड़), निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान हेतु ₹0 पचपन करोड़

(रु0 55.00 करोड़) तथा पर्यावरण मित्र बीमा हेतु रु0 दो करोड़ (रु0 2.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

19 (ख) आदरणीय अध्यक्ष जी, "ज्ञान" के दूसरे बिन्दु 'Y' अर्थात् युवा की सक्रिय और रचनात्मक भागीदारी प्रदेश के विकास की नींव है। शिक्षा, खेलकूद, कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार सृजन को केन्द्र में रखकर युवा शक्ति के लिए उम्मीदों से परिपूर्ण परिवेश का निर्माण किया जा रहा है। एक ऐसा प्रेरक परिवेश जहाँ युवा:—

रुकेंगें नहीं, थकेगें नहीं,

कठिनाईयों से, डरेंगें नहीं

आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगें।

- युवा नई सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा देकर, स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान रखकर, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी समझकर विकसित उत्तराखण्ड और विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे सकते हैं।
- युवा शक्ति को ध्यान में रखकर किये जा रहे कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:—
 - बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल व देहरादून में अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण कार्य गतिमान है।
 - हमारी सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की गयी है तथा बड़े पैमाने पर आधारभूत अवसंरचना व खेल उपकरणों की व्यवस्था की गई है।

- रोजगार हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने का अभूतपूर्व अभियान गतिमान है। पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया संचालित की जा रही हैं। बड़ी संख्या में नियुक्तियों का कीर्तिमान हमारी सरकार ने स्थापित किया है।
- राज्य के युवाओं को आधुनिक उद्योगों की माँग के अनुरूप प्रशिक्षित किये जाने हेतु 13 चिन्हित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा टेक्नोलॉजी प्रा०लि० के सहयोग से उच्चकृत प्रशिक्षण हेतु कार्यशालायें स्थापित की जा रही हैं।
- वर्ष 2024–25 में विकसित एकीकृत औद्योगिक संस्थानों में 45 औद्योगिक इकाईयां स्थापित हुई हैं, जिसमें 3,370 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है एवं लगभग 571 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।
- आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में “युवा शक्ति” हेतु कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किये गए हैं। कुछ प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:—
 - शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत समग्र रूप से प्रतिपूर्ति हेतु लगभग ₹0 एक सौ अठहत्तर करोड़ तिरासी लाख (₹0 178.83 करोड़), 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतु समग्र रूप से लगभग ₹0 उनसठ करोड़ इकतालीस लाख (₹0 59.41 करोड़), कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतु ₹0 तेईस करोड़ (₹0 23.00 करोड़), विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु ₹0 पन्द्रह करोड़ (₹0 15.00 करोड़), उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु ₹0 पन्द्रह करोड़ (₹0 15.00 करोड़), बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना हेतु ₹0 पन्द्रह करोड़ (₹0 15.00 करोड़), साइन्स

सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों हेतु लगभग रू० छब्बीस करोड़ चौंसठ लाख (रू० 26.64 करोड़), अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र हेतु रू० पाँच करोड़ पचहत्तर लाख (रू० 5.75 करोड़), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद हेतु लगभग रू० सोलह करोड़ अस्सी लाख (रू० 16.80 करोड़), उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान हेतु रू० पाँच करोड़ चालीस लाख (रू० 5.40 करोड़), विज्ञान केन्द्र चम्पावत हेतु रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़), विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु लगभग रू० दो करोड़ इकतालीस लाख (रू० 2.41 करोड़), राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय हेतु रू० दो करोड़ (रू० 2.00 करोड़), मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु रू० दो करोड़ (रू० 2.00 करोड़), एन०डी०ए० तथा आई०एम०ए० में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरस्कार हेतु लगभग रू० एक करोड़ पच्चीस लाख (रू० 1.25 करोड़), उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतु लगभग रू० सात करोड़ ग्यारह लाख (रू० 7.11 करोड़), टाटा टेक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद में रू० पैंतालीस करोड़ (रू० 45.00 करोड़) तथा पूंजीगत मद में रू० अठारह करोड़ (रू० 18.00 करोड़), उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति हेतु रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़), युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतु रू० पन्द्रह करोड़ (रू० 15.00 करोड़), युवा महोत्सव के आयोजन हेतु रू० पाँच करोड़ (रू० 5.00 करोड़), मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्बन योजना हेतु रू० पाँच करोड़ (रू० 5.00 करोड़), मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतु रू० दो करोड़ पचास लाख (रू० 2.50 करोड़), रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (RBI) हेतु रू० बीस करोड़ (रू० 20.00 करोड़), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू० साठ करोड़ (रू० 60.00 करोड़), मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु

रु० दस करोड़ (रु० 10.00 करोड़) तथा पं० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रु० इक्कीस करोड़ साठ लाख (रु० 21.60 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

19 (ग) अध्यक्ष जी, "ज्ञान" के तीसरे बिन्दु 'A' अर्थात् अन्नदाता की आयवृद्धि हमारी सरकार की प्राथमिकता है। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए पूर्व में कुछ प्रयासों का उल्लेख किया गया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है:—

- नई मांग के माध्यम से ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतु रु० एक सौ छियालीस करोड़ (रु० 146.00 करोड़) एवं आई.टी.बी.पी. बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना हेतु लगभग रु० तेरह करोड़ छियासठ लाख (रु० 13.66 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत समग्र रूप से रु० पिचासी करोड़ (रु० 85.00 करोड़), किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभग रु० बयालीस करोड़ अठारह लाख (रु० 42.18 करोड़), हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत रु० पन्द्रह करोड़ (रु० 15.00 करोड़), मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत रु० पैंतीस करोड़ (रु० 35.00 करोड़), दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूप से रु० तीस करोड़ (रु० 30.00 करोड़), गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत रु० पाँच करोड़ (रु० 5.00 करोड़), साईलेज आदि हेतु समग्र रूप से रु० चालीस करोड़ (रु० 40.00 करोड़), मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत रु० पच्चीस करोड़ (रु० 25.00 करोड़), मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु समग्र रूप से रु० बारह करोड़ तैंतालीस लाख (रु० 12.43 करोड़),

मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतु रू0 चार करोड़ (रू0 4.00 करोड़), स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु लगभग रू0 पाँच करोड़ पचहत्तर लाख (रू0 5.75 करोड़) तथा नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रू0 तीन करोड़ बाईस लाख (रू0 3.22 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

19 (घ) अध्यक्ष जी, अब 'ज्ञान' के अन्तिम बिन्दु 'N' अर्थात् नारी के आलोक में सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। हमारी सरकार का यह विश्वास है कि विकसित उत्तराखण्ड के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा। महिलाओं को कार्यबल से जोड़ना होगा। महिला सशक्तिकरण सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए जरूरी है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तो परिवार, समाज, प्रदेश और देश समृद्ध होगा।

- महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित कुछ प्रयासों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है:—
- हमारी सरकार द्वारा शिक्षा और जागरूकता अभियान, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन, महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करना एवं महिला नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा देकर नारी कल्याण के लिए गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं।
- सतत् विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलेपमेंट गोल्स) इंडिकेटर्स के लिए महत्वपूर्ण सूचकांक जैसे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव एवं लिंग अनुपात में सुधार के लिए सरकार गंभीरतापूर्वक प्रयत्न कर रही है।
- 'वर्क पॉपुलेशन रेशियो' में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। राज्य में महिलाओं के कार्य बल में सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से

आवश्यकतानुसार 06 माह से 06 वर्ष के शिशुओं की उचित देखभाल, सुरक्षा, पूरक पोषण, विकास, निगरानी, स्वास्थ्य जांच एवं स्कूल-पूर्व शिक्षा, आंगनबाड़ी-सह-क्रैच केन्द्रों में उपलब्ध करायी जा रही है। प्रथम चरण में दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 को जनपद देहरादून में सत्रह, हरिद्वार में तीन, टिहरी गढ़वाल में एक, पौड़ी गढ़वाल में एक तथा ऊधमसिंहनगर में बारह आंगनबाड़ी-सह-क्रैच केन्द्रों का शुभारम्भ किया गया है।

- राज्य के 5,120 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी में उच्चीकृत किया गया है। राज्य में 3,940 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।
- आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में नारी कल्याण हेतु कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रावधान किये गए हैं। जेंडर बजट में लगभग 16.66% की वृद्धि के साथ इस बजट में लगभग ₹0 सोलह हजार नौ सौ इकसठ करोड़ बत्तीस लाख (₹0 16,961.32 करोड़) का प्रावधान किया है। नारी कल्याण को समर्पित कुछ बजटीय प्रावधानों की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:-
- नन्दा गौरा योजनान्तर्गत लगभग ₹0 एक सौ सत्तावन करोड़ चौरासी लाख (₹0 157.84 करोड़), प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजनान्तर्गत लगभग ₹0 इक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख (₹0 21.74 करोड़), मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनान्तर्गत लगभग ₹0 उन्तीस करोड़ इक्यानवे लाख (₹0 29.91 करोड़), मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनान्तर्गत लगभग ₹0 बाईस करोड़ बासठ लाख (₹0 22.62 करोड़), मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लगभग ₹0 अठारह करोड़ अठ्ठासी लाख (₹0 18.88 करोड़), मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभग ₹0 तेरह करोड़ छियानवे लाख (₹0 13.96 करोड़), मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गत

रु० चौदह करोड़ (रु० 14.00 करोड़), मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रु० आठ करोड़ (रु० 8.00 करोड़), निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु रु० पाँच करोड़ (रु० 5.00 करोड़), मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत लगभग रु० तीन करोड़ छिहत्तर लाख (रु० 3.76 करोड़), मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु रु० पाँच करोड़ (रु० 5.00 करोड़), महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत रु० पाँच करोड़ (रु० 5.00 करोड़), राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोर्ड शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रु० चौदह करोड़ तेरह लाख (रु० 14.13 करोड़) तथा मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजनान्तर्गत रु० दो करोड़ (रु० 2.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

20. अध्यक्ष जी, हमारी नीतियों को जनता तक पहुँचाने और क्रियान्वित किए जाने में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। हमारी सरकार कार्मिकों के कल्याण के लिए निरंतर सजग है। इस वर्ष कर्मचारी हित में पदोन्नति तथा सेवानिवृत्तिक लाभ सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। कुछ प्रमुख बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:-

- हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय कार्मिकों को पहली बार कॉरपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण पहल की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत पर्सनल इंश्योरेंस कवर के साथ-साथ अन्य वित्तीय लाभों की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।
- हमारी सरकार द्वारा एलटीसी (LTC) हेतु न्यूनतम अवकाश की अवधि 15 दिन से घटाकर 5 दिन कर दी गई है तथा लेवल 1 से 5 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में वातानुकूलित श्रेणी-तीन (3rd AC), लेवल 6 से

9 तक के कार्मिकों को रेल यात्रा में वातानुकूलित श्रेणी-दो (2nd AC) तथा लेवल 10 या इससे अधिक वेतन पाने वाले कार्मिकों हेतु रेल यात्रा में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी (1st AC) अथवा हवाई यात्रा की अनुमन्यता प्रदान की गयी है।

- जून और दिसम्बर माह में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन में वित्तीय लाभ प्रदान करने के दृष्टिकोण से एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि (नोशनल) अनुमन्य की गई है।
 - राजकीय वाहन चालकों को प्रतिवर्ष रू0 3,000 वर्दी भत्ते की अनुमन्यता प्रदान की गई है।
21. आदरणीय अध्यक्ष जी, देवभूमि की आत्मा गाँवों में बसती है। विकसित गाँव के बिना विकसित उत्तराखण्ड की कल्पना नहीं की जा सकती है। गाँवों के विकास हेतु होम-स्टे, इको टूरिज्म, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, विद्युत व स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, सुगम व सुरक्षित संयोजकता, सुदृढ़ीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र, स्कूल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को विशेष ध्यान में रखना सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ गाँवों को विकसित बनाने की दिशा में किये जा रहे कुछ प्रयासों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है:-
- परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' पहल तथा लखपति दीदियों को केंद्र में रखते हुए "हाउस ऑफ हिमालयाज" ब्रांड का लोकार्पण किया गया है।
 - "हाउस ऑफ हिमालयाज" उत्तराखण्ड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व प्राकृतिक संपदा को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने का एक विकल्प रहित संकल्प है। स्वयं सहायता समूहों, महिला किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के प्रयासों को एकजुट करके उनके उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग को बेहतर बनाया जा रहा है।

- विकसित गाँव के लिए हमारी सरकार "विकास भी और विरासत भी" के मंत्र पर चलते हुए प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है। इसी क्रम में पर्वतीय क्षेत्रों में नौला (वाटर टैम्पल), धारा (स्प्रिंग) जैसी परम्परागत जल संचयन प्रणालियों को संकट से बचाने के लिए स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण (सारा) के तत्वावधान में कन्वर्जेन्स द्वारा जल स्रोतों के पुनरुद्धार हेतु कार्य किए जा रहे हैं।
- माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारकोट गांव (चमोली) को गोद लेकर एक आदर्श ग्राम बनाने की पहल की है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सारकोट के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य गतिमान है। सारकोट का यह मॉडल अन्य गाँवों के लिए प्रेरणा बनेगा। राष्ट्र कवि दिनकर जी की दो पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

मानव जब जोर लगाता है,

पत्थर पानी बन जाता है।

- ग्रामीण आजीविका के दृष्टिगत हमारी सरकार ने ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) को प्राथमिकता प्रदान की है। परियोजना के अन्तर्गत क्लस्टर फ़ैडरेशनों के माध्यम से गरीब परिवारों की आजीविका में वृद्धि किये जाने का उद्देश्य है।
- परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव को देश के प्रथम गांव की संज्ञा दी है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अन्तर्गत आज हमारे सीमान्त गाँवों का तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा राज्य के कुल 383 ग्रामों का चयन किया गया है। अभी तक 178 ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।

22. आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार गाँवों के साथ-साथ शहरी विकास के क्षेत्र में भी गम्भीर प्रयास कर रही है। अर्बन मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वॉटर रिसाइक्लिंग सिस्टम तथा अफोर्डेबल हाउसिंग आदि को विशेष ध्यान में रखा जा रहा है। प्रदेश में नवीन टाउनशिप विकसित किये जाने की दिशा में भी प्रयास किये जा रहे हैं। यहाँ शहरी विकास के क्षेत्र में किये जा रहे कुछ अन्य प्रयासों का उल्लेख किया जा रहा है:—

- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं यथा—ड्रैनेज, सड़क, नालियों का निर्माण, रैन बसेरों का संचालन, हाईटेक शौचालय का निर्माण एवं स्थानीय निकायों के पार्क आदि का निर्माण किया जा रहा है।
- राज्य में शहरीकरण की बढ़ोत्तरी के दृष्टिगत सभी आयवर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नई आवास नीति के प्रख्यापन का कार्य गतिमान है।
- योगनगरी ऋषिकेश को विश्व स्तरीय बनाये जाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। योगनगरी ऋषिकेश की स्वच्छता हेतु होलिस्टिक अप्रोच से कार्य किया जा रहा है।
- गोविन्द नगर (ऋषिकेश) में विगत वर्षों में एकत्रित हुए लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु ₹0 छः करोड़ पैंतालिस लाख (₹0 6.45 करोड़) की डी0पी0आर0 भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है। लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की पूर्ति रिंग फेंन्ड अकाउंट से तथा उक्त स्थल पर पार्क का सौन्दर्यीकरण व ओपन जिम आदि का निर्माण भी किया जाना विचाराधीन है।
- रुडकी, हरिद्वार, काशीपुर तथा देहरादून में भी लीगेसी वेस्ट निस्तारण का कार्य गतिमान है।

- इस बजट में शहरी विकास के अन्तर्गत पूंजीगत मद में लगभग ₹0 आठ सौ पचपन करोड़ पंचानवे लाख (₹0 855.95 करोड़) तथा आवास विकास विभाग के अन्तर्गत पूंजीगत मद में लगभग ₹0 दो सौ तैतालीस करोड़ (₹0 243.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
23. आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का यह विश्वास है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए प्रेरणादायी परिवेश होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था, राजकोषीय संतुलन तथा आवश्यक इको सिस्टम हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। विकास की गति को रोकने वाले अप्रासंगिक नियमों से मुक्ति दी जा रही है तथा सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण को कार्यनीति बनाया गया है। नवाचार विकास की सम्भावनाओं के नये द्वार खोल रहा है। गौरवशाली विरासत और विकसित उत्तराखण्ड का संकल्प हम सबको निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है।
24. आदरणीय अध्यक्ष जी, विकल्परहित संकल्प के मार्ग पर चलते हुए हमने अनेक प्रमुख योजनाओं हेतु इस बजट में प्रावधान किया है। कुछ योजनाओं का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है:—
- ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना अन्तर्गत ₹0 एक सौ पचास करोड़ (₹0 150.00 करोड़), राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु समग्र रूप से ₹0 पचपन करोड़ (₹0 55.00 करोड़), यूनीफार्म सिविल कोड (UCC) हेतु ₹0 तीस करोड़ (₹0 30.00 करोड़), परिवार पहचान पत्र उत्तराखण्ड योजना हेतु लगभग ₹0 दस करोड़ अठ्ठाईस लाख (₹0 10.28 करोड़), राज्य आन्दोलनकारियों को पेंशन हेतु ₹0 अड़तालीस करोड़ (₹0 48.00 करोड़), स्प्रिंग एण्ड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण (सारा) के अन्तर्गत राजस्व मद में ₹0 सताईस करोड़ (₹0 27.00 करोड़) एवं

पूँजीगत मद में रू० एक सौ करोड़ (रू० 100.00), अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु रू० पाँच सौ पचास करोड़ (रू० 550.00 करोड़), राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग रू० नौ सौ नवासी करोड़ चौहत्तर लाख (रू० 989.74 करोड़), संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान रू० छब्बीस करोड़ (रू० 26.00 करोड़), संस्कृत विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान रू० दो करोड़ (रू० 2.00 करोड़), सैनिक स्कूल घोड़ाखाल (नैनीताल) को अनुदान रू० पाँच करोड़ (रू० 5.00 करोड़), माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट कलस्टर विद्यालय निर्माण हेतु रू० चालीस करोड़ (रू० 40.00 करोड़), पशुपालन विभाग के अन्तर्गत ग्राम्य गौ-सेवक योजना हेतु रू० पचास करोड़ (रू० 50.00 करोड़) व गौ-संरक्षण को बढ़ावा हेतु रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़), शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत निराश्रित पशुओं व गौ-सदनों हेतु रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़), गैरसैण में अवस्थापना कार्य हेतु रू० बीस करोड़ (रू० 20.00 करोड़) तथा गैरसैण विकास परिषद को पूँजीगत परिसम्पत्तियों को अनुदान हेतु रू० पाँच करोड़ (रू० 5.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

25. आदरणीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष हम अनेक नई महत्वपूर्ण योजनाएं भी लेकर आये हैं। यहाँ कुछ योजनाओं में बजटीय प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है:—

- रिवर फ्रन्ट डेवलपमेंट परियोजना हेतु रू० दस करोड़ (रू० 10.00 करोड़), प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद हेतु रू० एक करोड़ (रू० 1.00 करोड़), यू.आई. आई.डी.बी. को परामर्शी सेवाओं एवं सर्विस सेक्टर सब्सिडी हेतु लगभग रू० एक सौ अड़सठ करोड़ तैंतीस लाख (रू० 168.33 करोड़), रेणुका जी बांध परियोजना मे राज्य की अंशपूँजी हेतु रू० दस करोड़

(रु० 10.00 करोड़) तथा स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु रु० छः करोड़ पचास लाख (रु० 6.50 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

- हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण नई योजनाओं जैसे मादक पदार्थों से सम्बन्धित अभियोग में कार्यवाही के लिए पुलिस कर्मियों आदि के उत्साहवर्धन हेतु रिवाल्विंग फंड की स्थापना, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, सैनिक विश्राम गृहों की साज सज्जा, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, आश्रम पद्धति विद्यालय में आई०टी० सेल का निर्माण, होमगार्ड कल्याण कोष आदि को प्रारम्भ कर रहे हैं।

26. आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट एक संकल्प है। यह संकल्प युगपुरुष परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सशक्त प्रेरणा से एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में सर्वांगीण और समावेशी विकास के साथ-साथ इस दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का द्योतक है। विकल्परहित संकल्प के मार्ग पर अडिग रहते हुए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूर्ण किये जा चुके हैं। 'यह संकल्प से सिद्धि का बजट है।'

यह बजट:

गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी कल्याण को समर्पित है,

गाँव और नगर की समृद्धि को समर्पित बजट है,

इकोनॉमी और इकोलॉजी को ध्यान में रखने वाला बजट है,

नवाचार, आत्मनिर्भरता व महान विरासत को

परिलक्षित करने वाला बजट है,

यह बजट ओजस्वी देवभूमि वासियों की आकांक्षाओं का बजट है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

“बह रही प्रगति की अविरल धारा,

नए आयाम छू रहा प्रदेश हमारा,

संकल्प सिद्ध हो रहा हमारा,

यह बजट है विकास की जनधारा।”

मैं, देवभूमि की महान जनशक्ति की सामूहिक ऊर्जा से सशक्त उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ:—

वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल प्राप्तियाँ लगभग ₹0 एक लाख एक हजार चौतीस करोड़ पचहत्तर लाख (₹0 1,01,034.75 करोड़) अनुमानित है, जिसमें ₹0 बासठ हजार पाँच सौ चालीस करोड़ चौवन लाख (₹0 62,540.54 करोड़) राजस्व प्राप्तियाँ तथा ₹0 अड़तीस हजार चार सौ चौरानवे करोड़ इक्कीस लाख (₹0 38,494.21 करोड़) पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व ₹0 उन्तालीस हजार नौ सौ सतरह करोड़ चौहत्तर लाख (₹0 39,917.74 करोड़) है, जिसमें केन्द्रीय करों में राज्यांश ₹0 पन्द्रह हजार नौ सौ दो करोड़ बयानवे लाख (₹0 15,902.92 करोड़) सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति ₹0 अठाईस हजार चार सौ दस करोड़ तीस लाख (₹0 28,410.30 करोड़) में कर राजस्व ₹0 चौबीस हजार चौदह करोड़ बयासी लाख (₹0 24,014.82 करोड़) तथा करेत्तर राजस्व ₹0 चार हजार तीन सौ पंचानवे करोड़ अड़तालीस लाख (₹0 4395.48 करोड़) अनुमानित है।

व्यय:

वर्ष 2025-26 में ऋणों के प्रतिदान (W.M.A./अर्थोपाय अग्रिम सहित) पर रू0 छब्बीस हजार पाँच करोड़ छियासठ लाख (रू0 26,005.66 करोड़), ब्याज की अदायगी के रूप में रू0 छः हजार नौ सौ नब्बे करोड़ चौदह लाख (रू0 6,990.14 करोड़), राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि पर लगभग रू0 अठारह हजार एक सौ सत्तानवे करोड़ दस लाख (रू0 18,197.10 करोड़), सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रू0 एक हजार चार सौ सैंतालीस करोड़ छब्बीस लाख (रू0 1,447.26 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रू0 नौ हजार नौ सौ सतरह करोड़ चालीस लाख (रू0 9,917.40 करोड़), व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2025-26 में कुल व्यय रू0 एक लाख एक हजार एक सौ पचहत्तर करोड़ तैंतीस लाख (रू0 1,01,175.33 करोड़) अनुमानित है। कुल अनुमानित व्यय में से रू0 उनसठ हजार नौ सौ चौवन करोड़ पैंसठ लाख (रू0 59,954.65 करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रू0 इकतालीस हजार दो सौ बीस करोड़ अड़सठ लाख (रू0 41,220.68 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि

वर्ष 2025-26 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है, अपितु रू0 दो हजार पाँच सौ पिचासी करोड़ नवासी लाख (रू0 2,585.89 करोड़) का राजस्व अधिशेष (सरप्लस) सम्भावित है। रू0 बारह हजार छः सौ चार करोड़ बयानवे लाख (रू0 12,604.92 करोड़) का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत है। यह एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत है।

वर्ष 2025–26 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष रू0 सत्तर करोड़ छियालीस लाख (रू0 70.46 करोड़) धनात्मक तथा वर्ष का अन्तिम शेष रू0 एक सौ उन्यासी करोड़ अठ्ठासी लाख (रू0 179.88 करोड़) धनात्मक रहना अनुमानित है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

मैं, मंत्रीमण्डल के अपने सहयोगियों के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं महालेखाकार, उत्तराखण्ड का आभारी हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय रूड़की तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

*ज्यों अविरल गंगा की धारा
करती सुशोभित प्रदेश हमारा
नित नये पग बढ़ रहा
सूरज विकास का चढ़ रहा*

इन्ही शब्दों के साथ, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वित्तीय वर्ष 2025–26 का आय–व्ययक प्रस्तुत करता हूँ:—

फाल्गुन 01, शक सम्वत् 1946

तदनुसार

20 फरवरी, 2025